



सत्यमेव जयते

REGIONAL CONFERENCE ON

“REPLICATION OF GOOD GOVERNANCE PRACTICES IN THE
UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR”

Organized By

Department of Administrative Reforms &
Public Grievances, Ministry of Personnel,
Public Grievances & Pensions
Government of India

Government of J & K

सुशासन संकल्प: कश्मीर घोषणा

ہی ہیل اع ری مشک : تمک حِ ماظن رتہب

Good Governance: Kashmir Resolution

JULY 1ST & 2ND, 2021

The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and the Government of Jammu & Kashmir organized the Regional Conference on **“Replication of Good Governance Practices in the Union Territory of Jammu & Kashmir”** in a semi-virtual mode at Srinagar on [July 1-2, 2021](#). The Regional Conference takes forward the learnings from the Regional Conference on **“Replication of Good Governance Practices in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh”** held at Jammu on [November 15-16, 2019](#), the Regional Conference on **“Ek Bharat Shresht Bharat with Focus on Jal Shakti and Disaster Management”** held at Jammu on [November 30-December 1, 2019](#), and the Regional Conference on **“Improving Public Service Delivery – Role of Governments”** held at Nagpur on [December 21-22, 2019](#).

In the years 2019-20 and 2020-2021, the DARPG and Government of Jammu & Kashmir have successfully collaborated in a number of administrative innovations. These include collaborations for digitalization of files, and implementation of e-Office in the Secretariat. Further the DARPG collaborated with the Government of Jammu & Kashmir for undertaking systemic improvements in the JK-IGRAMS which included integration of CPGRAMS with JK-IGRAMS, and integration of district portals with CPGRAMS enabling citizens to lodge grievances in a single portal. The integration of district portals with CPGRAMS represents the first such integration in India. The DARPG disseminated the Back to Village Scheme as a best practice in Administrative Innovations. The DARPG published a special edition of its journal Minimum Government – Maximum Governance on “Successful Innovations in Governance in the Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh”.

The National Centre for Good Governance has collaborated with IMPARD and IIPA, Jammu & Kashmir branch for capacity building programs for 450 civil servants of Government of Jammu & Kashmir.

The Regional Conference at Srinagar held on July 1-2, 2021 unanimously adopted the **Behtar Nizam e- Hakumat – Kashmir Aelamia** outlined below after extensive deliberations during the sessions held over two days.

The Regional Conference resolved that the Government of India and the Participating State Governments and the Union Territory of Jammu & Kashmir shall collaborate to:

ANNOUNCEMENTS:

1. The DARPG shall collaborate with Government of Jammu & Kashmir in developing a District Governance Index on the lines of the National Good Governance Index based on outcome and output indicators for improving the efficiency of Good Governance across Districts.
2. The DARPG shall collaborate with Government of Jammu & Kashmir for conducting capacity building programs for 2000 civil servants in Governance practices.
3. The DARPG shall collaborate with Government of Kashmir to conduct one National level conference and one Regional Conference in the period 2021-22.

For the Union Territory of Jammu & Kashmir:

1. To strengthen the sustained efforts to develop the Union Territory of Jammu & Kashmir as a model of administrative excellence

using digital technology in implementation of welfare state programs;

2. To continue the sustained efforts for transparent, accountable, efficient and people-centric administration in the Union Territory of Jammu & Kashmir by promoting Jan Bhagidari;
3. To refine, consolidate and document the successful good governance initiatives of the Union Territory of Jammu & Kashmir like Back to Village Scheme and JK-IGRAMS for national dissemination;
4. To replicate the innovations and best practices in successful national governance so as to improve the ease of living and provide a clean and transparent people centric governance to the UT of Jammu & Kashmir;
5. To continue the efforts for promoting e-Governance by use of e-Office and adopt version 7.0 and move towards paperless Secretariat in the Union Territory of Jammu & Kashmir;
6. To continue the efforts for capacity building and personnel administration by formulating mid-career training programs and specific need based training programs for officials of the Union Territory of Jammu & Kashmir by collaboration between the National Centre for Good Governance, the Institute of Management and Public Administration (IMPARD) and the Indian Institute of Public Administration, J&K regional branch;
7. To enable enhanced efficiency in decision making in the Government of the Union Territory of Jammu & Kashmir by process re-engineering, improved skill base and using technology as a force multiplier.

.....



**“संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में सुशासन प्रथाओं का
अनुकरण” पर
क्षेत्रीय सम्मेलन**

प्रशासनिक सुधार और लोक
शिकायत विभाग,
कार्मिक, लोक शिकायत और
पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार

जम्मू और कश्मीर सरकार

द्वारा आयोजित

सुशासन संकल्प : कश्मीर घोषणा

1 और 2 जुलाई, 2021

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा जम्मू और कश्मीर सरकार ने 1-2 जुलाई, 2021 को श्रीनगर में "जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सुशासन प्रथाओं का अनुकरण" विषय पर सेमी-वर्चुअल माध्यम से एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में जम्मू में 15-16 नवम्बर, 2019 को "जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में सुशासन प्रथाओं का अनुकरण" जम्मू में 30 नवम्बर - 01 दिसम्बर, 2019 को आयोजित "एक भारत श्रेष्ठ भारत, जल शक्ति एवं आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान केन्द्रण" एवं नागपुर में 21-22 दिसम्बर, 2019 को आयोजित "लोक सेवा प्रदायगी में सुधार - सरकारों की भूमिका" शीर्षकों के तहत आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त सीखों को आगे बढ़ाया गया है।

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं जम्मू और कश्मीर सरकार ने अनेक प्रशासनिक नवाचारों पर सफलतापूर्वक मिलकर काम किया है। इनमें फाइलों का डिजिटलीकरण करना एवं सचिवालय में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जेके-आईजीरैम्स में प्रणालीगत सुधार लाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ काम किया जिसमें सीपीजीरैम्स का जेके-आईजीरैम्स के साथ एकीकरण एवं जिला पोर्टलों का सीपीजीरैम्स के साथ एकीकरण शामिल था जिससे नागरिक अपनी शिकायतों को एक ही पोर्टल पर दर्ज करा सकें। जिला पोर्टलों का सीपीजीरैम्स के साथ एकीकरण भारत में इस प्रकार का पहला एकीकरण है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने "बैंक-टु-विलेज स्कीम" को प्रशासनिक नवाचारों में सर्वोत्तम प्रथा के रूप में प्रसारित किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने "जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में शासन में सफल नवाचार" विषय पर अपनी पत्रिका "न्यूनतम सरकार- अधिकतम शासन" का विशेषांक प्रकाशित किया।

सुशासन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र ने जम्मू और कश्मीर सरकार के 450 सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए आईएमपीएआरडी एवं आईआईपीए की जम्मू और कश्मीर शाखा के साथ मिलकर काम किया।

श्रीनगर में 1-2 जुलाई, 2021 को आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में 2 दिन तक तक चले सत्रों में व्यापक विचार-विमर्श के बाद बेहतर निजाम-ए-हुकूमत-कश्मीर अलेमिया को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जिसके बारे में नीचे बताया गया है।

क्षेत्रीय सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि भारत सरकार एवं सहभागिता करने वाली राज्य सरकारें एवं जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एक साथ मिलकर निम्नलिखित कार्य करेंगे :

घोषणाएं :

1. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग सभी जिलों में सुशासन की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए परिणाम और आउटपुट संकेतकों के आधार पर राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक की तर्ज पर एक जिला शासन सूचकांक विकसित करने में जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ सहयोग करेगा ।
2. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग शासन प्रथाओं में 2000 सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ सहयोग करेगा ।
3. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग वर्ष 2021-22 की अवधि में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन और एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए कश्मीर सरकार के साथ सहयोग करेगा ।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए :

1. कल्याणकारी राज्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रशासनिक उत्कृष्टता के एक मॉडल के रूप में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को विकसित करने के निरंतर प्रयासों को सुदृढ़ करना;
2. जनभागीदारी को बढ़ावा देकर संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और लोक-केंद्रित प्रशासन के लिए निरंतर प्रयास जारी रखना;
3. बैंक टू विलेज योजना और जेके-आईजीरैम्स की तरह ही संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की सफल सुशासन पहलों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार के लिए उन्हें संशोधित, समेकित और प्रमाणित करना;
4. संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में जीवनयापन सुविधाओं में सुधार लाने और इसे एक स्वच्छ और पारदर्शी लोक केन्द्रित शासन प्रदान करने के लिए सफल राष्ट्रीय शासन में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण।

5. ई-ऑफिस के उपयोग और संस्करण 7.0 को अपनाकर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखना और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कागज-रहित (पेपर-लेस) सचिवालय की ओर अग्रसर होना;
6. राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र, प्रबंधन ओर लोक प्रशासन संस्थान (आईएमपीएआरडी) और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय शाखा के सहयोग से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों के लिए मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके क्षमता निर्माण और कार्मिक प्रशासन के प्रयासों को जारी रखना ।
7. पुनःइंजीनियरिंग प्रक्रिया, उन्नत कौशल आधार पर बल गुणक (फोर्स मल्टीप्लायर) के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को निर्णयन प्रक्रिया की क्षमता बढ़ाने में समर्थ बनाना ।

کیم جولائی، 2021 کو سری نگر میں محکمہ انتظامی اصلاحات و عوامی شکایات (ڈی اے آر پی جی)، وزارت اہلکار، عوامی شکایات و پنشن اور حکومت جموں و کشمیر نے سیسی ور چول طرز پر "ریاست جموں و کشمیر کے خطے میں بہتر نظام حکومت کے طریقوں کی نقل" عنوان کے تحت ایک علاقائی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مذکورہ علاقائی کانفرنس نے اس دوران 15-16 نومبر، 2019 کو 'مرکزی ریاست جموں و کشمیر اور لداخ میں بہتر نظام حکومت کے طریقوں کی نقل' عنوان پر جموں میں منعقد ہوئی علاقائی کانفرنس، جموں میں ہی 30 نومبر سے کیم دسمبر، 2019 کو منعقد ہوئی علاقائی کانفرنس "جل طاقت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر ایک بھارت شریٹ بھارت کی توجہ" اور 21-22 دسمبر، 2019 کو "عوامی خدمت کی فراہمی میں بہتری - حکومتوں کا کردار" عنوان کے تحت ناگپور میں منعقد ہوئی علاقائی کانفرنس سے استفادہ بھی حاصل کیا۔

سال 2019-20 اور 2020-21 میں، محکمہ انتظامی اصلاحات و عوامی شکایات (ڈی اے آر پی جی) اور حکومت جموں و کشمیر نے متعدد انتظامی جدت کاری میں کامیابی کے ساتھ اشتراک کیا۔ ان میں فائلوں کی ڈیجیٹائزیشن، اور سیکرٹریٹ میں E-office ای آفس کے نفاذ کے لئے تعاون شامل ہیں۔ مزید (ڈی اے آر پی جی) نے JK-IGRAMS میں نظامی بہتری لانے کے لئے حکومت جموں و کشمیر کے ساتھ تعاون کیا جس میں CPGRAMS کے ساتھ JK-IGRAMS کا اشتراک، اور CPGRAMS کے ساتھ ضلعی پورٹلز کا انضمام شامل ہے جس سے شہریوں کو ایک ہی پورٹل میں شکایات درج کرنے کا اہل بنانا ہے۔ سی پی جی آر اے ایم ایس کے ساتھ ضلعی پورٹلز کا اشتراک بھارت میں اس طرح کے پہلے اشتراک کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈی اے آر پی جی نے

انتظامی جدت طرازیوں کا ایک بہترین عمل بیگ ٹو ویج اسکیموں کو عام کیا۔ ڈی آر پی جی نے اپنے جریدے "Maximum Governance-Minimum Government" میں "جموں و کشمیر حکومت میں بہترین طرز عمل" نام کا خصوصی ایڈیشن شائع کیا۔

بہتر نظام حکومت قومی مرکز نے جموں و کشمیر حکومت کے 450 سرکاری ملازمین کے لئے صلاحیت سازی کے پروگراموں کے لئے آئی ایم پی آر ڈی اور آئی آئی پی اے، جموں و کشمیر برانچ کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔

سری نگر میں منعقدہ علاقائی کانفرنس نے 1-2 جولائی، 2021 کو متفقہ طور پر بہتر نظام حکمت - کشمیر اعلامیہ کو دو دن سے زیادہ اجلاسوں کے دوران وسیع غور و خوض کے بعد طے کیا کہ مندرجہ ذیل امور پر حکومت ہند، شریک ہونے والی ریاستی حکومتیں اور مرکزی ریاست جموں و کشمیر تعاون کریں گے۔

اعلانات:

1- ڈی اے آر پی جی ضلع بھر میں بہتر حکومتی نظام کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے نتائج اور آؤٹ پٹ اشارات پر مبنی قومی بہتر حکومتی نظام انڈیکس کی خطوط پر ضلعی گورننس انڈیکس تیار کرنے میں حکومت جموں و کشمیر کے ساتھ تعاون کرے گا۔

2- ڈی اے آر پی جی حکومت جموں و کشمیر کے ساتھ حکومت کے طریقوں میں

2000 سرکاری ملازمین کے لئے صلاحیت سازی کے پروگراموں کے لئے تعاون کرے گی۔
3- ڈی اے آر پی جی حکومت کشمیر کے ساتھ مل کر ایک قومی سطح کی کانفرنس اور ایک
علاقائی کانفرنس 2021-22 کے دوران تعاون کرے گی۔
جموں و کشمیر کے مرکزی خطے کی ترقی کے لئے:

1- بہبود ریاست کے پروگراموں کے نفاذ میں ڈیجیٹل ٹکنالوجی کا استعمال کرتے
ہوئے یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر کو ترقی دینے کی مستقل کوششوں کو مضبوط بنانا۔
2- مرکزی ریاست علاقہ جموں و کشمیر میں جان بھاگیداری کو فروغ دے کر
شفاف، جوابدہ، موثر اور عوام کی بنیاد پر انتظامیہ کے لئے جاری کوششوں کو جاری رکھنا۔
3- قومی وسعت کاری اور دستاویز کاری کے ذریعے جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری
میں بہتر حکومتی نظام کے لئے بیک ٹولج اسکیم اور JK-IGRAMS جیسے پروگراموں کو
فروغ دینا۔

4- کامیاب قومی حکمرانی میں جدت اور بہترین طریقوں کی نقل تیار کرنا تاکہ زندگی
کو آسان اور بہتر بنایا جاسکے اور جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری میں صاف اور شفاف لوگوں پر مرکوز
حکمرانی مہیا ہو۔

5- E-Office کے استعمال سے E-Governance کو فروغ دینے کی
کوششوں کو جاری رکھنا اور 7.0 ورژن کو اپنانا تاکہ جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری میں کم
کاغذات کی ضرورت پڑے۔

6- نیشنل سینٹر فار گڈ گورننس، انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن (آئی

ایم پی اے ڈی) اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، جموں و کشمیر کی علاقائی برانچ۔
کے مابین باہمی تعاون کے ذریعے وسط کیریئر کے تربیتی پروگراموں اور جموں کشمیر یونین
ٹیریٹری کے عہدیداروں کے لئے مخصوص ضرورت پر مبنی تربیتی پروگرام تشکیل دے کر صلاحیتوں
کی تشکیل اور انتظامیہ کے اہلہ کاروں کے لئے کوششوں کو جاری رکھنا۔

7۔ ری۔ انجینئرنگ، ترقی یافتہ ہنرمندی کی بنیاد اور بطور قوت ضرب کی حیثیت سے
ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاسکے تاکہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں حکومتی فیصلے کرنے میں بہتر
کارکردگی کو قابل عمل اور بہتر بنایا جاسکے۔



सत्यमेव जयते

Department of Administrative Reforms & Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Government of India